Sl. No.	Name of State	Allocated strength	Allocation at +2 level	No. of Units at +2 level
17.	Mizoram	10,000	—	—
18.	Orissa	70,000	—	—
19.	Punjab	75,000	27,700	277
20.	Rajasthan	47,700	12,000	120
21.	Sikkim	3,000	—	—
22.	Tamil Nadu	1,40,000	50,000	1,000
23.	Tripura	6,000	—	—
24.	Uttar Pradesh	1,05,000	—	—
25.	West Bengal	30,000	15,800	158
26.	Andaman & Nicobar	250	—	—
27.	Chadigarh	6,000	1,000	10
28.	Delhi	36,300	32,000	320
29.	Pondicherry	4,500	3,400	34
30.	Lakshadweep	300	—	—
31.	Dadar & Nager Haveli	—	—	—
32.	Daman & Diu	—	—	—
		11,73,350	2,36,700	2,971

आलू की पैदावार बढ़ाना

749. **प्रो॰ राम लखन सिंह वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष खाद बीज एवं आधुनिक उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (ग) भारत सरकार किसानों को फसलों के उत्पादन के लिए जिसमें आलू भी शामिल है, नियंत्रण से मुक्त उर्वरकों की बिक्री पर म्यूरिएट आफ पोटाश तथा देशी डाई अमोनियम फासफेट पर, प्रत्येक पर प्रति टन 1000/-रुपए, सिंगल सुपर फासफेट पर प्रतिटन 340/- रुपए तथा देशी मिश्र उर्वरकों पर प्रति टन 435-999 रुपए (ग्रेड पर निर्भर करते हुए) की रियायत दे रही है। आलू सहित कन्दमूल फसलों के विकास की स्कीम के अंतर्गत उत्पादन लागत को कम करने तथा उत्पादकता को सुधारने के लिए ट्यूबर सीडस के स्थान पर टू पोटेटो सीड के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी सहयता दी जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत उत्पादित बीज मिनीकिट्स के माध्यम से रियायती दरों पर किसानों में वितरित किये जाते हैं। तथापि, इस समय आलू उत्पादन के लिए रियायती दरों पर आधुनिक उपकरण प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है।

उत्तर प्रदेश में यूरिया की आवश्यकता

750. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला-वार यूरिया की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता थी;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य को यूरिया की अनुमानतः कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) सरकार इस मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में यूरिया की जिले-वार खपत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) यूरिया की आवश्यकता का निर्धारण प्रत्येक फसल मौसम जैसे खरीफ (अप्रैल-सितम्बर) और रबी (अक्तूबर-मार्च) से पहले राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के परामर्श से किया जाता है। खरीफ, 1995 मौसम हेतु उत्तर प्रदेश में यूरिया की आवश्यकता 18.40 लाख मीटरी टन आंकी गई है। रबी, 1995-96 के लिए यूरिया का निर्धारण उपरोक्त पद्धति के अनुसार उचित समय पर किया जाएगा।

(ग) यूरिया की मांग स्वदेशी उत्पादन तथा आयात माध्यम से पूरी की जाती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में यूरिया की अनुपालित जिले-वार खपत

(टन में)

क्र॰ सं॰	जिला	1992-93	1993-94	1994-95
1.	सहारनपुर	84883	118688	79457
2.	मुजफ्फर नगर	131022	176928	133508
3.	मेरठ	95868	143807	102414
4.	गाजियाबाद	69180	94618	72636
5.	बुलन्दशहर	90606	96190	72636
6.	अलीगढ़	60786	65690	91040
7.	मथुरा	44139	44191	45472
8.	आगरा	40718	49285	61780
9.	मैनपुरी	23333	23860	40134
10.	इटा	57974	69229	74902
11.	बदायूं	107926	102264	125868
12.	बरेली	104038	79671	117674
13.	शाहजहांपुर	107302	106477	118551
14.	पीलीभीत	83243	81750	106352
15.	बिजनौर	102289	152690	107534
16.	मुरादाबाद	159125	193296	214383
17.	रामपुर	65338	83048	76908
18.	फर्रुखाबाद	78601	70758	82798
19.	इटावा	49125	43821	58358
20.	कानपुर (नगर)	7489	15352	21128
21.	फतेहपुर	53698	48057	67875
22.	इलाहाबाद	110216	89863	164995
23.	ललितपुर	10131	9865	10414
24.	झांसी	14604	11571	15382
25.	जालौन	20451	19833	27918
26.	हमीरपुर	13635	11710	9702
27.	बांदा	16143	12827	22829
28.	वाराणसी	103059	80480	84961
29.	मिर्जापुर	24955	20546	26856
30.	जौनपुर	35561	42658	66287
31.	गाजीपुर	75330	72909	89368
32.	बलिया	56607	63872	66295
33.	गोरखपुर	64029	77508	86790
34.	देवरिया	149458	161207	92918
35.	बस्ती	63025	79134	76569
36.	आजमगढ़	65836	57411	61558
37.	लखनऊ	33171	35829	37965
38.	उन्नाव	50617	42211	56628
39.	रायबरेली	48144	42956	55476
40.	सीतापुर	77091	82612	66653
41.	हरदोई	50316	47042	51540

क्र. सं.	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
42.	[illegible]	101519	116068	110813
43.	[illegible]	95712	135091	138776
44.	[illegible]	52036	54219	78457
45.	[illegible]	44073	40383	32324
46.	[illegible]	46694	40872	58825
47.	[illegible]	48353	43494	51224
48.	[illegible]	74822	63567	91892
49.	[illegible]	104950	101805	102623
50.	[illegible]	1412	935	688
51.	[illegible]	796	635	518
52.	[illegible]	5505	3424	4624
53.	[illegible]	657	335	206
54.	[illegible]	614	214	175
55.	[illegible]	13703	0	25118
56.	[illegible]	687	533	356
57.	[illegible]	45323	46698	49351
58.	[illegible]	28052	27599	34907
59.	[illegible]	44041	40222	35723
60.	[illegible]	29990	29748	42842
61.	[illegible]	8052	8372	8638
62.	[illegible]	21059	43363	55467
63.	[illegible] (देहात)	57074	11171	82715
64.	[illegible]	834	51516	225
66.	[illegible]	39125	8874	48606
	कुल :	3662705	3790852	4118726

U.N. Human Habitat Centre Scheme

751. SHRI SOM PAL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express dated 15th July, 1995 stating that Urban Development Scheme, which has been evolved by Human Habitat Centre of U.N. be implemented in metropolitan city of Madras;

(b) if so, the details of the main objectives of this scheme; and

(c) the details of the amount given to India as grant by the above named UN agency together with the details of locations where this amount is being utilised by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) Yes, Sir. the UNDP authorities have reported that in consultation with the Madras Metropolitan Development Authority and United Nations Centre for Human Settlement, UNDP have approved assistance of US $ 605,000 for Sustainable Madras Scheme. The scheme will be applicable to Madras and the project will support environmentally sustainable development and growth in Madras through multi-actor participation and partnership by: (a) strengthening local capacity to plan, manage and implement environment development interactions in the framework of broad-based participatory system and (b) promoting integrated and dynamically updated development plans and sector investment strategies leading directly to (c) banakable projects. A sister project of